Naidunia (Indore), 21st January 2025, Page- 03

व्याख्यान

आइआइटी इंदौर में नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला

नर्मदा नदी के पुनर्जीवन व प्रदूषण कम करने पर मंथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : नर्मदा नदी और आसपास क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी-इंदौर) के नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन अध्ययन केंद्र (सी-नर्मदा) द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला रखी। उसका विषय नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन के एकीकृत था। प्रदेशभर के विभिन्न संगठनों के कुल 48 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य नर्मदा नदी के पुनर्जीवन और उसके पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ बनाना था।

कार्यशाला में सात मुख्य व्याख्यान और कई पैनल चर्चा की गई। नर्मदा नदी के प्रदूषण को कम करने, जल प्रवाह को बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण, और कटाव नियंत्रण के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। नदी के किनारे पेड़ लगाने की आवश्यकता और जलाशयों में गाद को नियंत्रित करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय की सी-नर्मदा 'परियोजना का उद्देश्य नर्मदा नदी की पारिस्थितिकी को सुधारना व मानवीय गतिविधियों को कम करना है।

आइआइटी इंदौर में नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन पर कार्यशाला। • नईदुनिया

कार्यशाला में प्रो. मनीष कुमार गोयल ने नदी क्षेत्र प्रबंधन में आधुनिक उपकरणों के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर ही नदियों को निर्मल और अविरल बनाया जा सकता है। वहीं निदेशक प्रो. सुहास जोशी ने नर्मदा नदी प्रबंधन परियोजनाओं में छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में एक सहयोगी माडल विकसित किया जाना चाहिए। कार्यशाला में मिट्टी के कटाव, अवसादन, और जल गुणवत्ता पर चर्चा हुई। हिमालयी नदियों के केस स्टडी का उपयोग करते हुए नदी घाटियों में अवसादन की समस्याओं पर भी विचार किया गया।

एनसीए के सदस्य पावर आशीष दत्ता ने नदियों के सतत प्रबंधन में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नदियों के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और प्रशासन के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। प्रो. विनोद तारे ने नदियों को एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रबंधित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार, वर्षा जल संचयन, और चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया।